(DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) and (b). So far the students are concerned it may not be correct to say that education is becoming costlier day by day. Education in classes I-V is already free in government schools and in schools run by local bodies in all parts of the country. It is also free in Classes VI-VIII in all States except for boys in Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal. Here also these States propose to extend free education for boys upto the VIII shortly. Provided the necessary funds are available. Apart from this Government are providing scholarships, midday meal and other concessions at various levels. It is also helping in establishing Book Banks and in providing papers etc. to produce cheaper textbooks and stationeries. However, the general costs of articles have gone up with the rise in the normal cost of living and Government are aware of the needs to keep down the cost of education especially for the vulnerable sections of the population. The Government investment in education has increased considerably alongwith the efforts in the recent years to reduce the costs for the students.

नये कालेज खोलने के बारे में नीति

1723. **श्री केशवराव घोंडगे** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने राज्यों ने नये कालेज स्थापित करने के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजे हैं और इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : नये कालेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है । सरकार का विचार है कि उस शिक्षा से सम्बन्धित सुविधाओं का विस्तार अनियोजित ढंग से नहीं किया जाना चाहिए और यह कि नये कालेज स्थापित करने से पहले उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष की उच्च शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का पर्याप्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए ।

विश्वपुरी, महाराष्ट्र में उठाऊ सिंचाई योजना

1724. **श्री केशवराव घोंडगे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा डिवीजन में नन्देड के निकट विश्वपुरी के लिए उठाऊ सिंचाई योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) इस योजना का कार्य बन्द कर देने के क्या कारण हैं जब कि इस के लिए धनराशि मंजूर की जा चुकी है ; और

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार को इस योजना पर कार्य न शुरू करने का निदेश दिया है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख): लोअर गोदावरी परियोजना, (इश्तपुरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम) की जिसे नन्देड के निकट स्थित विश्वपुरी के लिए लिफ्ट सिंचाई स्कीम भी कहा जाता है; परियोजना रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से केन्द्रीय जल आयोग में अक्तूबर, 1975 में प्राप्त हुई थी । केन्द्रीय